देहरादून (उत्तराखण्ड)
सोमवार 16.02.2026
समय 18.30

मुख्य समाचार :–

- मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने टिहरी झील को ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किये जाने के लिये प्रभावी कार्ययोजना बनाये जाने के निर्देश दिये।
- औली में आयोजित राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिप और विंटर कार्निवाल संपन्न। हिमाचल प्रदेश ने 6 स्वर्ण पदकों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया।
- सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में निर्माणाधीन सैन्य धाम के अंतिम चरण के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी निर्माण कार्यों को तय समयसीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए।
- **और,** पिथौरागढ़ की प्रसिद्ध ट्राउट मछली अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बनाने जा रही है। मत्स्य विभाग ने ट्राउट मछली को दुबई निर्यात करने की प्रक्रिया शुरू की।

टिहरी झील

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने टिहरी झील को ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किये जाने के लिये प्रभावी कार्ययोजना बनाये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने सचिव पर्यटन को उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के स्तर पर टिहरी झील एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने को कहा। उन्होंने अवस्थापना सुविधाओं के विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व टिहरी लेक डेस्टिनेशन का पर्यटन के दृष्टिगत विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करने के भी निर्देश दिये।

मुख्य सचिव ने कहा कि टिहरी लेक को ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किये जाने संबंधी प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजा जाए। मास्टर प्लान तैयार करने के लिये अनुभवी कन्सलटेन्ट की नियुक्ति की जाए। मुख्य सचिव ने टिहरी लेक के चारों ओर रिंग रोड तैयार करने की कार्ययोजना में तेजी लाये जाने, प्रस्तावित सी प्लान योजना के साथ रिंग रोड पर कम से कम दो हेलीपैड बनाए जाने की व्यवस्था के भी निर्देश दिये। इसके लिये उन्होंने सचिव वित्त से सचिव पर्यटन, नागरिक उड्डयन और लोक निर्माण से समन्वय कर योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिये। मुख्य सचिव ने कहा कि टिहरी लेक को ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में पहचान दिलाने के लिये आवश्यक है कि यहां पर विश्व स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास हो।

मॉडल फैसिलिटी

राजकीय दून मेडिकल कॉलेज को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन–एबीडीएम की मॉडल फैसिलिटी के रूप में तैयार किया जाएगा। व्यवस्थाएं सुचारू कराने के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण व कालेज प्रशासन की संयुक्त बैठक में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। लाभार्थियों को कतारों से मुक्ति दिलाने के लिए अस्पताल में एबीडीएम का पृथक काउंटर लगाने और परिसर में जागरूकता गतिविधियों पर जोर दिया गया। मेडिकल कालेज के चिकित्सा अधीक्षक डा रविंद्र सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में एबीडीएम की प्रबंधक प्रज्ञा पालीवाल ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशों के अनुरूप दून मेडिकल कॉलेज को एबीडीएम की मॉडल फैसिलिटी के रूप में प्रस्तुत किया जाना है। यहां मरीज क्यूओर

कोड के जरिए स्कैन एंड शेयर व स्कैन एंड पे के जरिए पंजीकरण व भुगतान करेंगे, कार्मिकों के हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री–एचपीआर को अनिवार्य किया गया है।

आपदा प्रबंधन

उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन के गुर सीखने में बेटियां भी बेटों से पीछे नहीं हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से युवा आपदा मित्र योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें अभी तक 1826 युवाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिसमें 874 बेटियां शामिल हैं। उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से संवेदनशील है। यहां पर आपदा से निपटने के लिए कई स्तर पर प्रयास चल रहे हैं। इसके अलावा आपदा के प्रभावों को कम करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।

औली समापन

चमोली स्थित विश्वप्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थली औली में आयोजित राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिप और विंटर कार्निवाल 2026 का आज भव्य समापन हो गया। देशभर से आए खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदकों के साथ पहला स्थान हासिल किया। सेना की टीम 3 स्वर्ण पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि जम्मू–कश्मीर ने 2 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। हिमाचल प्रदेश की एथलीट ने अपने राज्य के शानदार प्रदर्शन पर खुशी जताई और औली में किए गए प्रबंधों की सराहना की।

सैन्य धाम की समीक्षा

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में देहरादून के गुनियाल गांव में निर्माणाधीन सैन्य धाम के अंतिम चरण के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान मंत्री जोशी ने लोकार्पण से पूर्व सभी निर्माण कार्यों को समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि सैन्य धाम केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि वीर शहीदों के सम्मान और प्रदेश की गौरवशाली सैन्य परंपरा का प्रतीक है, इसलिए कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सैनिक कल्याण मंत्री ने अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि लोकार्पण कार्यक्रम गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। उन्होंने कहा कि सैन्य धाम उत्तराखंड के वीर जवानों के शौर्य और बलिदान को समर्पित है और यह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्थल बनेगा।

कार्यों की समीक्षा

केंद्र सरकार द्वारा कारोबार में सुगमता बढ़ाने के लिए गठित टास्क फोर्स की अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सचिव मीता राजीव लोचन एवं मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (फेज 2) के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सचिव मीता राजीव लोचन ने बताया कि उत्तराखंड ने डी–रेगुलेशन 1.0 कम्प्लायंस रिडक्शन में देश में पांचवां स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सिंगल विंडो सिस्टम, लैंड यूज, होम स्टे और उद्यमिता एवं श्रम सुधारों के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयोगों की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य के लिए फेस–2 के तहत नौ प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। जिसमें राज्य को भूमि उपयोग, भवन एवं निर्माण की स्वीकृति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, पर्यावरण, पर्यटन के क्षेत्र में नवाचार, जैसी प्राथमिकताएँ शामिल हैं। इन प्राथमिकताओं का उद्देश्य राज्य में विकास कार्यों को और गति देना, निवेश और आधारभूत ढांचे को और अधिक मजबूत करना तथा नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराना है।

आर्थिकी का साधन

पिथौरागढ़ की प्रसिद्ध ट्राउट मछली अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बनाने जा रही है। राज्य सरकार की पहल पर मत्स्य विभाग ने ट्राउट मछली को दुबई निर्यात करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही इसका पहला कंसाइनमेंट दुबई भेजा जाएगा। दुबई में आयोजित इंटरनेशनल एक्सपो में शामिल होकर लौटे मत्स्य विभाग के सहायक निदेशक डॉ रमेश सिंह चलाल ने बताया कि वहां की कई कंपनियों और मीट एक्सपोर्टरों के साथ सकारात्मक बातचीत हुई है। दुबई के बाजार में उत्तराखंड की ट्राउट मछली की गुणवत्ता और स्वाद को लेकर विशेष रुचि दिखाई गई है और इसे लेकर विभाग निर्यात की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने बताया कि ट्राउट मछली का निर्यात शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के मत्स्य पालकों की आय बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।

जनता मिलन

चम्पावत कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जनसमस्याएं सुनीं। कार्यक्रम में 83 शिकायतें दर्ज की गईं। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनता मिलन कार्यक्रम में मुख्य रूप से आर्थिक सहायता, आवास, पेयजल, सोलर लाइट, आपदा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण योजनाओं की मरम्मत, जंगली जानवरों से फसल सुरक्षा के लिए तारबाड किए जाने के मुद्दे उठाए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि आम नागरिक को अपनी बुनियादी समस्याओं के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।

महत्वाकांक्षी परियोजना

पहाड़ों की रानी मसूरी में लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देहरादून से मसूरी के बीच यातायात को सुगम बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। देहरादून से मसूरी तक लगभग 3500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत दो लेन हाईवे बनाए जाएंगे. इसके लिए केंद्र सरकार ने औपचारिक मंजूरी दे दी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के निदेशक सौरभ सिंह के अनुसार 3500 करोड़ से बनने वाले इस 42 किलोमीटर लंबे दो–लेन हाईवे के एलाइनमेंट को केंद्र सरकार ने औपचारिक मंजूरी दे दी है। यह नया रूट झाझरा से शुरू होकर मसूरी के लाइब्रेरी चौक तक जाएगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पर्यटन नगरी मसूरी के लिए एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध करना है, ताकि मौजूदा सड़कों पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सके। इस नेशनल हाईवे की सबसे बड़ी खासियत इसमें बनने वाली दो अत्याधुनिक सुरंगें होंगी।

सहकारिता मंत्री

सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत गुजरात के गांधीनगर में 17 फरवरी को आयोजित होने जा रहे देशभर के राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक में प्रतिभाग करेंगे। यह बैठक केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित होगी। इस बैठक में डॉ. रावत 'सहकार से समृद्धि' को लेकर राज्य सरकार की योजनाओं और भविष्य के रोडमैप को रखेंगे और अपने सुझाव साझा करेंगे।

एआई दक्षता

प्रदेश के शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस–एआई में दक्ष बनाने के लिए राज्य सरकार सतत व्यावसायिक विकास–सीपीडी कार्यक्रम विकसित करेगी। इसका उद्देश्य उन्नत डिजिटल तकनीक से शिक्षकों को लैस करते हुए कक्षा शिक्षण को एआई आधारित नवाचारों से जोड़ना है, ताकि छात्रों के अधिगम परिणामों में सुधार लाया जा सके। भविष्य की शिक्षा प्रणाली में एआई की बढ़ती भूमिका को देखते हुए राज्य स्तर पर एक समग्र रणनीति तैयार की जा रही है। इसके तहत शिक्षकों को डिजिटल प्रशिक्षण मॉड्यूल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और इंटरेक्टिव टूल्स के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में एआइ के बुनियादी सिद्धांत, डेटा आधारित शिक्षण, व्यक्तिगत अधिगम–पर्सनलाइज्ड लर्निंग और मूल्यांकन विश्लेषण जैसे विषय शामिल होंगे। उत्तराखंड अकादमी शोध एवं प्रशिक्षण निदेशक बंदना गर्ब्याल ने कहा कि एआई को शिक्षकों के सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बनाने का संकल्प लिया गया गया है।

सरपंचों की बैठक

चमोली में जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में जिले के सरपंचों की ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से विभिन्न मांगों के निराकरण के संबंध में बैठक हुई। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग सर्वेश कुमार दुबे ने सरपंचों की विभिन्न मांगों एवं विभाग से संबंधित सभी जानकारी जिलाधिकारी को दी। उन्होंने बताया कि जिले में वन प्रभागों द्वारा अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 तक बंदरों का बान्ध्यीकरण को मिले 2700 लक्ष्य के सापेक्ष 1703 बंदरों को बान्ध्यीकरण के लिए हरिद्वार भेजा गया। साथ ही मानव वन्य जीव संघर्ष घटनाओं से सम्बंधितों को भुगतान दिया जा रहा है। शेष लंबित प्रकरणों को और बजट अवमुक्त होने पर भुगतान किया जाएगा। जिले में 852 वन पंचायत कार्यरत हैं, जिनमें से 304 वन पंचायतों में चुनाव होना शेष है एवं वनाग्नि से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।